(i) भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति

(ii) भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति

(iii) भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति

(iv) भारतीय राष्ट्रीय चट्टान यांत्रिकी एवं सुरंग प्रौद्योगिकी समिति

(v) भारतीय राष्ट्रीय निर्माण सामग्री एवं संरचना समिति

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित समितियों ने भी अनुसंधान व विकास प्रस्तावों/योजनाओं की सिफारिश की है:

(i) शिक्षा व प्रशिक्षण संबंधी स्थायी समिति

(ii) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

(iii) भूकम्प अभिकल्पना पैरामीटर संबंधी राष्ट्रीय समिति

निम्नलिखित सरकारी संगठनों ने भी अनुसंधान व विकास प्रस्तावों/योजनाओं की सिफारिश की है:

(i) केन्द्रीय जल आयोग

(ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड

(iii) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

(घ) वार्षिक योजनाएं 1993-94 एवं 1994-95 के लिए जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के वास्ते क्रमशः 5.67 करोड़ रुपए एवं 6.70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है।

Representation from SC/ST for Inclusion in OBC

2622. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the people/organisation belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes expressing their rejection to abandon their present status and demand for their inclusion in the OBC; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Representations bave been received from All India Nepali Scheduled Castes Association, Darjeeling; Hill Scheduled Castes/Tribes Welfare Organisation, Darjeeling; Bengal Scheduled Castes and Tribes Federation, Darjeeling and All India Scheduled Castes/Scheduled Tribes Bank Employees Federation.Calcutta not to de-schedule Kami (Nepali), Damai (Nepali) and Sarki (Nepali) communities from the Scheduled Caste list of West Bengal and also not to specify these communities as Other Backward Classes as demanded by Gorakha National Liberation Front; Another representation has been received from Namasudra Samaj Kalyan Samity, Nowrangpur, Orissa not to deschedule Namasudra community from the existing Scheduled Caste list of Orissa as against the decision of the State Govern mem of Orissa to include the community in other Backward Class list.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में निरक्षरता

2623. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गुजरात राज्य के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और (घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जाति/जनजाति में साक्षरता की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, साक्षरता आंकड़े दस वर्ष में एक बार आयोजित किए गए नियमित जनगणना के अंतर्गत एकत्र किए गए हैं। पिछली जनगणना 1991 में की गई थी।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति की साक्षरता दरें विवरण-I पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा विवरण-II पर गुजरात के संबंध में जिलावार दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।